Offer from Canadian Commercial Corporation for Rajmahal open cast coal mines in Bihar

3040. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Canadian Commercial Corporation, a state owned company has offered equipments and services worth 166 million Canadian dollars for the expansion of the Rajmahal open cast coal mines in Bihar;

(b) if so, whether the company has made an agreement to this effect with the Coal India Limited;

(c) if so, what are the terms and conditions of the agreement; and

(d) by when the work is likely to be completed?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Canadian Commercial Corporation has undertaken to implement the expansion of the Rajmahal Open cast Project from 5 million tonnes to 10.5 million tonnes per annum on a turnkey basis within 66 months with performance guarantees for coal quantity and quality, for timely completion within specified costs and for achieving high productivity. The cost of the Canadian goods and services worth 166 million Canadian dollars will be covered by a concessional credit from Export Development Corporation of Canada. The Commercial contract and the Loan Agreement were signed in January, 1989.

(d) July, 1994.

Training to officials of developing countries by BHEL

3041. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) has proposed to train some officials from developing countries in the operation and maintenance of power plant equipments;

(b) if so, what are the reasons for not giving training to Indians; and

(c) what are the details in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Five persons from Nepal were trained for a period of 4 weeks in the Operation and Maintenance of Turbines and Generators. Assistance in training has also been offered to pesonnel from some developing countries like Malaysia, Indonesia, Guyana, Gambia and Swaziland.

(b) and (c) Training to personnel of utilities and industries in India is being given by BHEL as a regular practice. During 1988-89 about 300 persons have availed of training in various BHEL units. In addition, experts are deputed to various sites for discussions/familiarisation on requests from the customers.

एच०बी० जे० पाइप लाइन से गैस की पूर्ति

3042. **ठाकुर जगतपाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 21 नवम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1343 के दिए गए उत्तर देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि एच० बी० जे० पाइप लाइन से किन-किन राज्यों को अतिरिक्त गैस की कितनी कितनी मात्रा वितरित की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मूल रूप में एच० बी० जे० पाइप लाइन के द्वारा 6 उर्वरक संयंत्रों (4 उत्तर प्रदेश में एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश में और दो गैस पर आधारित बिजली घरों (एक राजस्थान में और एक उत्तर प्रदेश में) को गैस की सप्लाई करने की परिकल्पना की गई थी। बाद में एन टी पी सी

के दादरी में प्रस्तावित बिजली घर, दिल्ली में देसू के बिजलीघर तथा कानपुर में आई०ई०एल० के उर्वरक संयंत्र को नियमित आधार पर गस सप्लाई करने का निणय लिया गया ।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

3043. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण के संबंध में महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समाचार में यह बताया गया है कि विशेषतया महिलाओं और निर्धन व्यक्तियों पर, जिनके लाभ के लिए इस संस्थान की स्थापना की गयी है, अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समाचार का पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ।

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस रिपोर्ट में महिलाओं की अधिक सक्रिय और सहयोगी भूमिका और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शामिल किए गए अधिक लाभकारी उद्योगों में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । रिपोर्ट में महिलाओं को कम और अलाभकारी मजदूरी का भुगतान करने, श्रम संबंधी नियमों का पालन न करने, शैडों में किए जाने वाले कार्य में महिलाओं के लिए सहायक सेवाओं की कमी जैसे प्रतिकूल कारकों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

इस अध्ययन को पूरे खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के कार्य-क्लापों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए । खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यकलापों से काफी हद तक महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा है । खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में महिलाओं का भाग 46% और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का 32% है । सहायता की उदार पद्धति को जो पहले पहाडी/सीमावर्ती/पिछड़े क्षेत्रों/कमजोर वर्गों में लागू थी, अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लागू कर दी गई है बशर्ते कि वे गरीबी की रेखा के नीचे आते हों । सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन किया है जिसमें ग्रामोद्योग के कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया गया है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 1988-89 से विकास के लिए 34 नए उद्योगों का पता लगाया है । कुछ नए ग्रामोद्योगों में टेलरिंग, सिले-सिलाए वस्त्रों, वनों पर आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक रोजगार प्रदान करेंगे ।

Reduction of bulk drug prices

3044. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Indian drug Manufacturers' Association has complained that the recent reduction of certain bulk drug prices, without considering the norms prescribed by the Drug Price Control Order, 1987, would make the bulk drug industry sick; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) A complaint of the Indian Drug Manufacturers' Association is related to the reduction of the price of Rifampicin bulk drug. A Committee has already been constituted to look into the matter.